

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4051
सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

4051. श्री राजेश नारणभाई चुडासमा:

श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान श्रमिकों के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय सहायता का गुजरात सहित वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजना से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजना/कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से अपने प्रयासों में सहयोग के लिए अनुरोध किया था; और
- (घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय केंद्र प्रायोजित तीन योजनाओं नामतः राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन आदि का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना और एनसीएस पोर्टल के साथ रोजगार कार्यालयों को जोड़ने हेतु उनके प्रस्तावों के आधार पर एनसीएस के विभिन्न घटकों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमसीसी और एनसीएस योजना के इंटरलिंगिंग घटकों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (गुजरात सहित) को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

| वित्तीय वर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (21.03.2022 तक) |
|---|---------|---------|---------|-------------------------|
| राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां | 761.98 | 2595.12 | 896.73 | 42.31 |
| गुजरात को जारी की गई निधियाँ | 0 | 35.27 | 0 | 0 |

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 8.92 लाख अभ्यर्थियों को करियर परामर्श/व्यावसायिक मार्गदर्शन/आत्मविश्वास निर्माण/भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह राज्य/संघ राज्य सरकारों के सहयोग से किया गया है।
